श्री अनुपम श्रीवास्तव, सीएमडी, बीएसएनएल का टेलीएनालीसिस के साथ चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा :–

बीएसएनएल 2–3 वर्षों के समय में रूपया 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में रक्षा विभाग हेतु एनएफएस, बीबीएनएल के लिए नोफेन, एलडब्ल्यूई उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों तथा नार्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए सम्मिलित हैं। नार्थ ईस्ट प्रोजेक्ट के अतिरिक्त सभीपरियोजनाओं में कार्य प्रारंभ है। **चरण 7 तथा 8 में मोबाइल का विस्तारः** चरण 7 में 15 लाख अतिरिक्त सामर्थ्य वृद्धि के लिए रूपया 4804 करोड़ का निवेश होगा। यह अतिरिक्त सामर्थ्य 2 जी तथा 3 जी दोनों का ध्यान रखेगा। इस चरण में बीएसएनएल 27,000 टावर्स स्थापित करेगा जिसमें 2जी का 15,000 तथा 12,000, 3जी का होगा। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 97,000 टावर्स हैं। इस चरण में 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष जून 2015 तक पूर्ण होगा। चरण 7 विस्तार 2जी की कमी तथा मोबाइल नेटवर्क को दूर करेगा। डाटा कैपेसिटी में 30–40 गुना की वृद्धि होगी। मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर में चरण 8 में कार्य हो रहा है। चरण 8 में चार भाग हैं। प्रथम भाग वाई–फाई इन्टेग्रेशन पर केन्द्रित होगा। दूसरे भाग में डाटा कैपेसिटी में वृद्धि का होगा। तीसरे भाग में प्रक्रिया रोमिंग पर केन्द्रित होगी।जिसमे कि अन्य ऑपरेटर्स से 2जी तथा 3जी की भागेदारी में सहायक प्रमाणित हो। अन्तिम भाग में 2जी तथा 3जी की गुणवत्ता विकास पर ध्यान होगा। **ग्राहकों के लिए सहायक सेवाएंः** मोबाइल सेवाओं के लिए 20 सर्किलों में 18 कॉल सेन्टर्स हैं। सीएफए विभाग के लिए भी कॉल सेन्टर्स की योजना बन रही है। जिससे कि ग्राहकों की शिकायतों तथा वैल्यू एडेड आदि सेवाओं पर ध्यान दिया जाय। सीडीआर बिलिंग की भी योजना फिक्सड फोन्स, मोबाइल तथा लीज्ड लाईनों पर ध्यान देगा।

वाई–फाई कैसे बीएसएनएल को सहायता देगा ?

बीएसएनएल के पास कॉपर केबिल तथा ऑप्टिकल फाईब का भंडार है। इनका डाटा सेवाओं में उपयोग होगा। वाई–फाई हॉट्स्पाट्स को 3जी सेवाओं से जोड़ा जाएगा जिससे मोबाइल ग्राहकों से सुगमता से सम्पर्क हो सकेगा। डाटा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि टेलीकॉम उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है। यदि स्ट्रेटजी ठीक रही तो इसमें हम सफल होंगें। दो–तीन वर्षों में 2500वाई–फाई हाट्स्पाट्स की योजना है। इसके लिए बीएसएनएल ने क्वादजेन वायरलेस से दक्षिण तथा पश्चिम में रेवेन्यू भागीदारी के आधार पर कार्य करना है। वाई–फाई कवरेज के लिए शीघ्र ही उत्तर तथा पश्चिम रीजन्स का टेन्डर करेगें।

टॉवर लीजिंग तथा लैन्ड बैकः टॉवर लीजिंग (किराए पर देने) का मामला संचार मंत्रालय को भेजा गया है। एक पृथक सब्सिडियरी टॉवर कम्पनी बीएसएनएल में बनना है जो कि सरकारी कम्पनी की होगी। ज्वाइन वेन्चर का सृजन होगा। लैन्ड बैंक (भूमि बैंक) के 8 प्रस्ताव संचार मंत्रालय को भेजे गए हैं। इसमें भवन निर्माण कॉम्पलेक्स, आईटी पार्क तथा कमर्शियल भवन योजनाएं है। अनुमोदन लम्बित है।

वर्ष 2014–2015 का अनुमोदित रेवेन्यूः 4.5 प्रतिशतवृद्धि के साथ अनुमोदित रेवेन्यू रूपया 29,000 करोड़ है। वर्ष 2018–19 तक कम्पनी लाभ में आ जाएगी।

उत्पादकता के आधार पर प्रोत्साहन पीएलआई

पीएलआई की संयुक्त समिति की बैठकें दिनांक 12 मार्च,2015 के अपरान्ह में वरिष्ठ महाप्रबंधक ;एसआरद्ध की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रशासन के पक्ष से सीनियर जीएम ;स्थापनाद्ध, जीएम ;लेख स्थापनाद्ध तथा जीएम पुनर्गठन ने भाग लिया। प्रारंभ में जीएम पुनर्गठन ने बताया कि **कर्मचारी पक्ष के इस**

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है कि उत्कृष्ट, बहुत उत्तम, के साथ–साथ फार्मूले में सुन्दर भी सम्मिलित किया जाएगा। प्रशासन पक्ष का यह प्रस्ताव भी आया कि प्रक्रिया में अधिकारियों के संघों को भी सम्मिलित किया ताय। एनएफटीई नेदो टूक शब्दों में कहा कि इस समिति का गठन नान–इक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को प्रोत्साहन धन हेतु है। इसमें नेशनल कौंसिल के लीडर तथा सचिव को समिति में शामिल किया गया हे। अतः अन्य वर्ग के संघों को सम्मिलित करने का औचित्य नहीं है। प्रशासन पक्ष ने बताया कि जहाँ तक मोबाइल वीएलआर का प्रश्न है वह डीओटी–बीएसएनएल के एमओयू पर आधारित होगा। एनएफटीई ने दृढ़ता के साथ न्यूनतम पीएलआई (बोनस) की मांग रखी। अग्रिम प्रक्रिया हेतु आवश्यक है कि प्रबंधन न्यूनतम पीएलआई राशि निर्धारित करे। कर्मचारियों को इस संबंध में अंधकार में रखना उचित नहीं है। डीपीई के निर्देशनों के आधार पर कर्मचारियों को पीएलआई का भुगतान करनाचाहिए जिससे कि कर्मचारी प्रोत्साहित हो। प्रशासन पक्ष ने कहा कि मांग को निदेशक तथा सीएमडी को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सम्मेलन में साथी राजीव वर्मा, संजय दुबे तथा अशोक राय अध्यक्षता, प्रांतीय मंत्री तथा खजान्ची निर्वाचित हुए है।

बीएसएनएल–एमटीएनएल का निजीकरण नहीं

संचार मंत्री ने राज्य सभा में घोषणा किया कि उपक्रमों का निजीकरण नहीं होगा अपितु इन्हें लाभ में लाने का प्रयास है। दोनो कम्पनियों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। इस पर एक दिन वृहत चर्चा की जाएगी। सेवा में सुधार हेतु बीएसएनएल–एमटीएनएल 25,000 टावर्स लगा रहे हैं।

राज्य सभा में प्रश्न 1822 का 13.2.2015 का निम्नवत उत्तर दिया गया है।

ए. बीएसएनएल में 2,25,785 नियमित तथा 3469 दैनिक मजदूर कार्यरत है।

डी व ई. 25 वर्ष से अधिक :153 15–25 वर्ष तक : 2213, 5–15वर्ष तक : 1089

उच्चतम न्यायलय के श्रीमति उमादेवी बनाम अन्यों मेंनिर्णयानुसार नियमितीकरण सम्भव नहीं है।

टेम्पोरेरी स्टेट्स

टेम्पोरेरी स्टेट्स मजदूरों का बीएसएनएल में सम्मिलित होने पर पीओ जारी होना. बीएसएनएल 269–2/2011–पीए/एलई/वॉल्यूम 111दिनांक 13 मार्च, 2015 सभी सीजीएम्स को सभी सर्किलों से पुनः अनुरोध है कि शेष टीएसएमस का 31.3.3015 तक विवरणी भेज दें। इसे पश्चात् कोई भी मामला लाम्बित नहीं रहना चाहिए।

बीएसएनएल बोर्ड में लम्बित मुद्दों का समाधान नहीं होना

टीएफ –21/6(डी) दिनांक 10.3.2015 सीएमडी, बीएसएनएल को

प्रबंधन समिति की अनुशंसा के उपरांत निम्न मुद्दों को बोर्ड में अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अधिक समय व्यतीत हो गया है परन्तु मुद्दों का समाधान अभी तक लम्बित है।

1.निगम में 1.1.2007अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में कमी।
2. बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों के पेंशन नियम
3. जेटीओ वर्ग का भर्ती नियम
4. जेएओ वर्ग में प्रोन्नति परीक्षा हेतु 5 वर्ष की सेवा शर्त
5. एनईपीपी में ई–1 स्केल

संघ को पता चला है कि बोर्ड में डीओटी अधिकारियों के विरोध के कारण अनुमोदन नहीं हुआ है। इससे औद्योगिक शांति प्रभावित हो रही है।

कृपया हस्तक्षेप करें जिससे कि समाधान सुनिश्चित हो।

सीएचक्यू से संकलित अंश.....सुरेशराव थोपटे